Pioneer Hindi
Prakratik kheti aaj samay ki zaroorat ban chuki hai: Amitabh Kant
Apr 26, 2022 | Delhi | Pg No.: 10 | Bottom Center | Bureau | Sq Cm: 253 | AVE: 394578 | PR Value: 1972890

प्राकृतिक खेती आज समय की जरूरत बन चुकी है : अमिताभ कांत

भाषा। नई दिल्ली

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने प्राकृतिक खेती को समय की जरूरत बताते हुए सोमवार को कहा कि इस समय रसायनों और उर्वरकों के उपयोग के कारण खाद्यान्न उत्पादन की लागत बढ़ गई है। कांत ने नीति आयोग की तरफ से नवाचार कृषि पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब गेहूं और चावल का निर्यातक बन चुका है। हालांकि, अकुशल आपूर्ति शृंखला और अधूरे बाजार संपर्कों के कारण भारत की कृषि क्षेत्र की उत्पादकता कम है। उन्होंने कहा, प्राकृतिक खेती समय की जरूरत है और यह महत्वपूर्ण है कि हम वैज्ञानिक तरीकों की पहचान करें ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि किसान इससे सीधे लाभान्वित हों और उनकी आमदनी बढ़े। कांत ने कहा, रसायनों और उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण खाद्यान्नों और सब्जियों के उत्पादन की लागत बढ़ गई है। प्राकृतिक खेती में रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसे कृषि-पारिस्थितिकी पर आधारित खेती की विविध प्रणाली के रूप में देखा जाता है। यह जैव विविधता के साथ फसलों, पेड़ों और मवेशियों को भी समाहित करते हुए चलती है।

भारत में कुछ लोगों को ही अवसर मिलने का कहानी अब अब बदल चुकी है: चंद्रशेखर

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही अवसर होने की पुरानी कहानी अब बदल चुकी है और पुराने कारोबारी समूहों से एकदम अलग नई कंपनियों के जगह बनाने से इसकी झलक भी मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री चंद्रशेखर ने पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया (पीएएफआई) के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में जाति के आधार पर विभाजन होने के कारण केंद्र में हमेशा एक कमजोर सरकार रही जिसके मूल में परस्पर-विरोधी हितों वाला गठबंधन होता था। उन्होंने कहा कि नब्बे के दशक की शुरुआत में यह आख्यान गढ़ा गया था कि भारत में अवसर कुछ ही लोगों के लिए हैं। उन्होंने कहा, वह कहानी 2010-12 तक चलती रही। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के बैंकों ने 97 फीसदी कर्ज नौ कारोबारी समूहों को दिए थे। वह एक तरह से पूंजी को एक तरफ ढकेलने की कोशिश थी। जिसमें कुछ ही लोगों के बीच अवसरों का संकेंद्रण था। वह कई दशकों से भारत की एक निहित कहानी थी लेकिन आज वह बदल चुकी है।

चालू वित्त वर्ष में घरों के दाम आठ प्रतिशत, कीमत 12 प्रतिशत बढ़ेगी: इंडिया रेटिंग्स

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष में आवास की कीमतों में आठ प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह बढ़त मुख्य रूप से अंतिम उपयोगकर्ताओं से मांग में वृद्धि के कारण हो सकती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने यह अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में कहा, घरों की बिक्री में आया उछाल और बढ़ी हुई मांग अंतिम उपयोगकर्ता की वजह से है। इसलिए कीमतों में वृद्धि टिकाऊ है और यह बढ़ रही है। बीते वित्त वर्ष में अखिल भारतीय स्तर पर घरों की कीमतें छह प्रतिशत बढ़ी थीं। रेटिंग एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में कहा, घरों की बिक्री में आया उछाल और बढ़ी हुई मांग अंतिम उपयोगकर्ता की वजह से है।

कोल इंडिया की अनुषंगी बनी रहेगी सीएमपीडीआई: सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को जोर देते हुए कहा कि सीएमपीडीआई कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी बनी रहेगी और वह इसका मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्प लिमिटेड (एमईसीएल) के साथ विलय करने पर विचार कर रही है। सरकार की तरफ से यह बयान दरअलस सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट (सीएमपीडीआई) के एमईसीएल के साथ विलय करने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की खबरों के बीच आया है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अन्य खनिजों में अपने व्यापार विस्तार की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीएमपीडीआई को मजबूत करने की योजना बनाई है। इसके लिए एमईसीएल के सीएमपीडीआई में विलय करने पर विचार किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, एमईसीएल के पास गैर-कोयला खनिज खोज और परामर्श में विशेषज्ञता है। इस तरह का विलय कोयला और गैर-कोयला क्षेत्र के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के साथ एकीकृत खोज को बढ़ावा देगा। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अन्य खनिजों में अपने व्यापार विस्तार की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीएमपीडीआई को मजबूत करने की योजना बनाई है।